524

दृष्टि The Vision

drishti

GENERAL STUDIES (Test–18)

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

GSM (M-I)-2418

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250

Name: Ritik Arya **Mobile Number:** [redacted]

Medium (English/Hindi): HINDI **Reg. Number:** 3094

Center & Date: M.N, 21/08/24 **UPSC Roll No.** ***(If allotted)*:** 0808386

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
*इसमें **बीस** प्रश्न हैं तथा **हिन्दी** और **अंग्रेज़ी** दोनों में छपे हैं।*
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।
प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:
*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and **ENGLISH.***
All the questions are compulsory.
The number of marks carried by a question is indicated against it.
Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.
Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.
Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा भरा जाए *(To be filled by Evaluator only)*

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Reviewer (Signature)

drishti | दृष्टि The Vision

Feedback

1. Context Proficiency (संदर्भ दक्षता)
2. Introduction Proficiency (परिचय दक्षता)
3. Content Proficiency (विषय-वस्तु दक्षता)
4. Language/Flow (भाषा/प्रवाह)
5. Conclusion Proficiency (निष्कर्ष दक्षता)
6. Presentation Proficiency (प्रस्तुति दक्षता)

---

1. संसदीय उत्तरदायित्व के स्तर को निर्धारित करने में विपक्षी दलों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। चर्चा कीजिये।

(150 शब्द) 10

The role of opposition parties is critical in determining the level of parliamentary accountability. Discuss.

(150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत मे ब्रिटेन की तरह संसदीय व्यवस्था अपनायी गई है। साथ मे यहाँ प्रतिस्पर्धीय दलीय व्यवस्था पायी जाती है। वर्तमान 18 वीं लोकसभा मे इंडिया गठबंधन संसद मे विपक्ष की भूमिका मे प्रमुख है।

लाभ →

- सरकार को कल्याणकारी नीतियों के निर्माण मे मार्गदर्शन, आलोचना करके कमियाँ बताना
- वित्त विधेयक के समय कटौती प्रस्ताव, विनियोग विधेयक पर सवाल करके सरकार को गैर-जिम्मेदराना व्यय से रोकना।
- समितियों मे यथा लोक लेखा आदि के विधेयकों, CAG रिपोर्ट की जांच

- विभिन्न प्रस्ताव यथा- ध्यानाकर्षण द्वारा महत्वपूर्ण मामले पर ध्यान खींचना, निंदा प्रस्ताव द्वारा मंत्री या सरकार की निंदा करना।

- सरकार जब अल्पमत मे हो तो अविश्वास प्रस्ताव पेश करना।

- विपक्ष के नेता के लिए (1/10 सीटें) की आवश्यकता होती है जो सरकार को लगातार दिशानिर्देशित करता रहता है

चुनौतियाँ
→ रचनात्मक आलोचना की जगह राजनीतिक स्वार्थ
→ काम मे बाधा, धरना, स्पीकर को परेशान करना (वर्तमान संसद मे काम के घण्टे 1950 → 126 घण्टे से 2024 → 60 घण्टे)

अतः विपक्ष को ब्रिटेन की तरह शैडो कैबिनेट का निर्माण और जर्मनी की तरह रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। विपक्ष लोकतंत्र को जिन्दा रखने मे सहायक है

2. महिलाओं की श्रम बल भागीदारी को बढ़ाने में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10
Discuss the role of Self-Help Groups in widening women's labour force participation. (150 words) 10

वर्तमान मे भारत मे महिला श्रम भागीदारी दर 25% (2018) से बढ़कर 37% हो गयी है। जबकि ग्लोबल स्तर पर 47% है। ऐसे मे स्वंय सहायता समूह इसमें उल्लेखनीय कार्य कर सकती है।

स्वंय सहायता समूह से आशय महिलाओं का ऐसा समूह जिसमें आपस मे लगान हो, समता निर्माण करने मे सहायक हो और सूक्ष्म वित्तीयन द्वारा अपनी आर्थिक जरूरत पूरी करती हो। भारत मे SHG मे 85-90% महिलाएँ ही हैं।

1992 में बैंक की सहायता से SHG-Bank लिंकेज कार्यक्रम चला।

इसने आर्थिक व सामाजिक सशक्तीकरण में सहायता की |

श्रम बल बढ़ाने में SHG

① सखी रिटेल जैसे समूह इन्हें आपस में जोड़कर आर्थिक सशक्त बनाते है

② यह महिलाओं को घर पर ही अपने गांव में कार्य उपलब्ध कराती

③ सूक्ष्म वित्तीयन के द्वारा इन्हें पूंजी की समस्या नहीं रहती |

कुछ चुनौतियाँ
- पूरे भारत में सफल नहीं
- सूक्ष्म वित्तीयन का पैसा प्रधान, सचिव ले लेते
- राजनीति से ग्रस्त
- पुरुष प्रधान (पितृसत्तात्मकता)
- निजी बैंक लोन नहीं देते

अतः वर्तमान में SHG इन चुनौतियों को दूर करते हुए महिला सशक्तीकरण व महिला श्रम भागीदार बढ़ाकर जेंडर गैप को दूर कर सकते है |

3. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलने से समाज के कल्याण के प्रति समग्र दृष्टिकोण को बल मिला है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

The approach to welfare is wholesome and whole-of-society, with increasing private sector participation through Corporate Social Responsibility(CSR). Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

कंपनी अधियनियम 2013 मे निजी कंपनी जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ या शुद्ध लाभ 5 करोड़ से ज्यादा है उन्हें 2% CSR समाज के लिए तथा 1% अपने कर्मचारियो के लिए करने का प्रावधान है।

इसने कारपोरेट गवर्नेंस मे सहायता तथा समाज के कल्याण को सरकार के साथ-2 निजी क्षेत्र को भी सौंपा है। चूँकि कंपनियाँ समाज और पर्यावरण तथा यहाँ के लोगो से ही व्यापार करती लाभ कमाती है तो यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है।

समाज के कल्याण के कार्य

→ विद्यालयों, कॉलेजों की स्थापना
  ↳ जैसे TISR
  ↳ अग्रवाल - वेदांता कॉलेज

→ झारखण्ड, उड़ीसा में उद्योगों ने CSR द्वारा जनसहायता के लिए स्कूल, अस्पताल खोले

→ वैज्ञानिक शोध (R&D) में सहायता

→ आपदा के समय सहायता
  जैसे अभी हाल में टाटा द्वारा वायनाड में.

↓ NGO सिविल सोसायटी को सहायता
जैसे- अजीम प्रेमजी द्वारा

कुछ चुनौतियाँ
→ ① कंपनियाँ स्वेच्छा की जगह बाध्यता से करती तो भ्रष्टाचार करती
→ ② इसे अपने सगे संबंधियों के NGO में सहायता देती

अतः वर्तमान में यह एक अच्छा प्रयास है जो कल्याणकारी राज्य (अनु. 37) का क्रिया-वयन करता है तथा निजी व पब्लिक दोनों की जिम्मेदारी तय करता है

4. व्यक्तिगत और राष्ट्रीय विकास के क्रम में मानसिक स्वास्थ्य, कम ध्यान दिये जाने वाला लेकिन प्रभावशाली चालक है। चर्चा कीजिये। इस संबंध में सरकार की सकारात्मक नीति क्या है? (150 शब्द) 10

Mental health is a less seen yet principally impactful driver of individual and national development. Discuss. What is the Government's positive policy momentum in this regard? (150 words) 10

कोविड के बाद मानसिक स्वास्थ्य दुनिया मे चर्चा का मुद्दा है। WHO ने "My Health My Right" कैम्पेन मे इसे आवश्यक माना है।

मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चुनौती

① भारत जैसे देशो 1% से कम लोग ध्यान देते

② यहाँ Anxiety depression का मजाक बनाया जाता

③ सायकेट्रिस्ट की संख्या 10 मिलियन पर 100-120 के लगभग जो बहुत कम

④ सरकार अपना ज्यादा स्वास्थ्य बजट संक्रामक, व कैन्सर टीबी जैसी बीमारियो पर खर्च करती

ऐसे मे आज यह बड़ी समस्या बनकर उभरा है जहाँ

उचित काउन्सलिंग और अध्यात्म की जरूरत है

सरकार की नीति

- सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधि० 2016 में 21 प्रकार में मानसिक ~~विकार~~ विकलांगता को जोड़ा।
- 'मानस' पहल द्वारा 24×7 हेल्पलाइन नं०
- कोविड के बाद किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अस्पतालों में शिविर आयोजित
- उपभोक्तावाद के दुष्प्रभाव से बचने के लिए योगा, अध्यात्म का प्रचार
- पर्यावरण से जुड़ने की पहल

अतः सरकार के साथ-2 नागरिक समाज व व्यक्ति स्वयं को आगे आकर मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए कार्य करना चाहिए।

5. ग्रामीण भारत के शासन में सुधार हेतु शुरू की गई विभिन्न डिजिटलीकरण पहलों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

Discuss the multiple digitization initiatives that have been unfolding in rural India to improve governance. (150 words) 10

डिजिटलीकरण ई-शासन का एक स्तम्भ है। यह सरल, सुलभ व तेज माध्यम है। 2015 की डिजिटल भारत पहल के तहत यह तेजी से प्रसार कर रहा है।

ग्रामीण भारत → डिजिटलीकरण पहल

- भारत नेट → ऑप्टिकल फाइबर द्वारा भारत के 6.5 लाख गांवो को नेट से जोड़ना।
- भूमि अभिलेखो के डिजिटलीकरण
  - ↳ वर्तमान मे ड्रोन से परीक्षण
- ई-पोर्टल, ई-शिक्षा, ई-चिकित्सा द्वारा लोगो तक शासन व सुविधाओ को पहुंचाना।

- डिजिटल इण्डिया साक्षर मिशन
  ↳ यह डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए है।

- DBT के द्वारा पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त नगद हस्तांतरण
  जैसे → किसान सम्मान निधि

- JAM ट्रिनिटी द्वारा वित्तीय समावेशन

- पंचायतो को नेट से जोड़ने के लिए पंचायत राज मंत्रालय कम्प्यूटर व तकनीक उपलब्ध करवा रहा।

- RTI द्वारा पंचायतो मे पारदर्शिता

अत: अभी भी डिजिटल डिवाइस, मोबाइल, फण्ड की कमी के कारण कुछ चुनौती है परंतु सरकार के वर्तमान प्रयास प्रशंसनीय है जो डिजिटल इण्डिया को दिखाता है।

6. भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस लिखित संघीय संविधान को नम्यता (Flexibility) प्रदान करने का प्रयास किया गया है। विस्तारपूर्वक समझाइये। (150 शब्द) 10

A distinctive feature of the Indian Constitution is that it seeks to impart flexibility to a written federal Constitution. Elaborate. (150 words) 10

भारतीय संविधान दुनिया का बेहतरीन व समय के साथ प्रसंगत रहे इस प्रकार से निर्मित किया गया है। इसी का लक्षण उसकी कठोरता के साथ नम्यता है

नम्यता के उपबंध

- अधिकांश संशोधन जो महत्वपूर्ण है जैसे - राज्य निर्माण, संसदीय कार्यवाही आदि साधारण विधेयक से हो जाते।
- बजट में वित्त चाहे धन विधेयक हो साधारण विधे. से पारित
- संविधान का हर भाग संशोधित किया जा सकता है (1973 केशवानंद भारती केस:- सिर्फ B.S. होड़कर)

- कानून या अधिनियम बनने के बाद कार्यपालिका उस पर उपनियम या निर्देश अपनी इच्छानुसार बना सकती है

अनु॰
- 123 अध्यादेश कार्यपालिका को विशेष स्थिति मे विधेयक को अधि॰ बनाने की छूट देता है
- सप्लीमेंटरी डिमांड आदि सरकार को वित्त की सुगमता पहुंचाते है

परंतु फिर भी संविधान का मूल ढाँचा सरकार नही बदल सकती। सरकार ऐसे कानून नही बना सकती जो मूल अधिकारों को कम करें। इसके अलावा विशेष संशोधन के 2/3 समर्थन + राज्यों (50% +1) का समर्थन आवश्यक है

अतः भारतीय संविधान बहुत ही संतुलित तरीके से निर्मित है

7. न्यायिक कार्यों की पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता एक सुदृढ़ एवं प्रभावी विधिक प्रणाली की आधारशिला है, जिससे लोक विश्वास सुनिश्चित और न्यायिक सिद्धांत का कार्यान्वयन संपुष्ट होता है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

The transparency and accountability of judicial function form the cornerstone of a robust and effective legal system, ensuring public trust and upholding the principles of justice. Discuss. (150 words) 10

भारत मे शक्ति का प्रथक्करण पाया जाता है जहाँ न्यायालय की स्वतंत्रता व पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा गया है। यह संविधान के संरक्षक के रूप मे कार्य करती है।

न्यायालय का महत्व

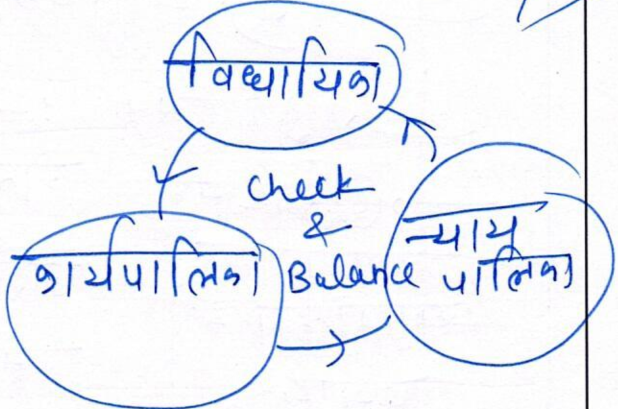

① PIL जैसी याचिका को स्वीकृति देने से न्यायालय भी सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है।

② यह मौलिक अधिकारो का रक्षक और सरकार को निरंकुश होने से रोकता (SC → Art 32
HC → Art 226)

न्यायालय पर आरोप

- ① कोलेजियम सिस्टम पारदर्शिता और सामाजिक न्याय के विपरीत
- ② भाई-भतीजावाद का आरोप
- ③ न्यायाधीश अपनी संपत्ति जाहिर नहीं करते
- ④ न्यायिक विधायन
- ⑤ अनु. 142 पूर्ण न्याय का
- ⑥ RTI नहीं गलत उपयोग

न्यायालय के प्रयास

- पारदर्शिता के लिए ई-कोर्ट और लाइव प्रसारण
- कोलेजियम में न्याया. का तर्क है कि इसमें विधि मंत्रालय, IB Report शामिल होती है और न्यायिक स्वतंत्रता के आवश्यक
- स्थानीय भाषा में निर्णय (ई-भाषा एप)

अतः न्यायालय को पारदर्शी व न्यायिक संयम के साथ लोगों के विश्वास को बनाए रखना चाहिए।

8. राज्यों की राजनीतिक कार्यप्रणाली के संबंध में राज्यपालों के गैर-पक्षपातपूर्ण बने रहने से संबंधित संवैधानिक अवधारणा गहन जाँच के दायरे में है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

The constitutional conception of state governors occupying a non-partisan position with regard to the political functioning of states has come under severe strain. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

अनु. 153 मे संविधान मे राज्यपाल के पद का प्रावधान है जो एक साथ दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है, वह राज्य का संवैधानिक मुखिया और केन्द्र का राज्य मे एजेन्ट होता है

वर्तमान मे राज्यपाल को लेकर चुनौती

① केन्द्र की तरफ झुकाव तथा विपरीत दलों वाले राज्यों मे राज्य सरकार का समर्थन नही करना जैसे → तमिलनाडु, बंगाल के आरोप

② विधेयको को लगातार रोके रखना, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेना (अनु. 200)

जैसे → DMK का नीट बिल को लेकर

③ अनु. 164 राज्यपाल को विवेकाधिकार देता है जिसका दुप्रयोग।

④ त्रिशंकु चुनाव में भेदभाव करना

⑤ राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप

⑥ मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य न करना

⑦ यूनिवर्सिटी के चांसलर को लेकर विवाद

सुझाव

→ सरकारिया आयोग
↳ राज्यपाल सक्रिय राजनीति वाला नहीं

→ पुंछी आयोग
↳ राज्यपाल, मुख्यमंत्री से सलाह नियुक्ति में

↓ SC ने कहा राज्यपाल को एक समय सीमा के अंदर विधेयक पर निर्णय

↓ SR बोम्मई केस
↓ पटल पर विश्वासमत

अतः वर्तमान विवाद राजनीतिक ज्यादा संवैधानिक कम प्रतीत होते हैं जहां संयम की जरूरत है।

9. "कारागार सुधार न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है, बल्कि एक विधिक एवं सामाजिक आवश्यकता भी है।" इस कथन के आलोक में भारत में कारागारों की स्थिति का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द) 10

"Prison reform is not just a moral imperative, but a legal and social necessity." In light of this statement, critically analyze the state of prisons in India. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारत मे वर्तमान मे कारागार अत्यधिक बुरी अवस्था मे है यह राज्यसूची का विषय है। 130% ओवर क्षमता के साथ चल रहा है

चुनौती / आलोचना

① अत्यधिक घनत्व

② पूरे भारत मे मानवाधिकारों की समस्या
- → जेलो मे हत्या
- → हिंसा
- → बलात्कार

(जैसे → अभी कोलकाता मे महिला कैदी बलात्कार मामला)

③ किशोर कारागार में बच्चों में सुधार की जगह अपराध की प्रवृत्ति ज्यादा हो रही।

④ बेसिक आवश्यकताओं की कमी जैसे- भोजन, दवाई, स्वच्छ जल

⑤ महिला जेलों में समस्या तथा उनके साथ रहते बच्चे (लगभग 1लाख बच्चे)

सुधार → ~~ब~~ NHRC की रिपोर्ट लागू
- → प्रकाश सिंह वाद की अनुशंसा
- → जेलों की संख्या बढ़ाना
- → कैदियों का मानव संसाधन के रूप में प्रयोग

अतः जेल सुधार गृह की तरह कार्य करने चाहिए न कि उत्पीड़न गृह की तरह।

10. भारत में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए इसके कार्यान्वयन संबंधी प्रमुख मुद्दों एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालिये। (150 शब्द) 10

Discuss the need for an All-India Judicial Service (AIJS) in India, highlighting key issues and challenges in its implementation. (150 words) 10

भारतीय संविधान के अनु. 315 मे अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का प्रावधान है। 99 वें संविधान संशोधन द्वारा सरकार एक प्रावधान लायी जिसे SC ने रद्द कर दिया फिलहाल वो कॉलेजियम से संबंधित था। तो ऐसे मे AIJS को लेकर →

चुनौतियाँ → एवं मुद्दे

① न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित

② राज्य सूची व संघवाद की समस्या क्योंकि निचली अदालते राज्य का विषय

③ एकल न्यायपालिका मे बाधा

④ फण्ड व अवसंरचना की कमी

लाभ

① आरक्षण लागू सभी का प्रतिनिधित्व

② भाई-भतीजावाद खत्म

③ पारदर्शिता बढ़ेगी

④ सामाजिक न्याय

⑤ केस सुलझाने में ज्यादा मशीनरी

⑥ पूरे भारत में न्याय की एक मशीनरी

अतः राज्यसभा अनु. 249 द्वारा AIJS की सिफारिश कर सकती है परंतु उससे पहले SC/HC से सलाह को सलाह अवश्य करनी चाहिए

11. सराहनीय प्रयासों के बावजूद, भारत की जनजातीय जनसंख्या तक स्वास्थ्य सेवाओं के सफल वितरण में विभिन्न चुनौतियाँ विद्यमान हैं। विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

Despite commendable efforts, there are several obstacles that hinder the successful delivery of healthcare services to the tribal population of India. Analyse. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत मे वर्तमान मे 8.6% जनजातीय संख्या निवास करती है/ यह भारत की सबसे पिछड़ी और शोषित आबादी है जिसने आजादी के पहले अंग्रेजो से अनेक संघर्ष किए। वर्तमान मे इनका स्वास्थ्य भी चिंता का विषय है –

चुनौतियाँ →

① सिकिल सेल एनीमिया का प्रभाव → मध्यप्रदेश की भील जनजाति मे यह अत्यधिक बड़ी समस्या

② कुपोषण, स्टंटिंग, वेस्टिंग जनजातीय बच्चो मे ज्यादा।
80-90% जनजातीय बच्चे कुपोषित

③ एनीमिया → जनजातीय महिलाओं मे 60%.

④ जटिल व चुनौतीपूर्ण क्षेत्र जहाँ यह निवास करते है तो पहुँच मुश्कल जैसे - दण्डकारण्य पहाड़

⑤ विभिन्न भ्रांतियाँ, अन्धविश्वास

↳ जनजाति समाज कई बार दवाइयों को अन्धविश्वास की वजह से नही अपनाता

⑥ प्रशासन का ढीला रवैया।

↳ अधिकांश प्रशासन जिला या तहसील स्तर पर रहते है तो उनमे कल्याण का अभाव

⑦ अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी

↳ जिससे ये स्वास्थ्य के महत्व को नही समझते।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(D) पूर्वाग्रह व रूढ़िवादिता

सरकार के प्रयास

→ आजादी के बाद इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट द्वारा प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा

→ वर्तमान में 2023-24 बजट में सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक खत्म करने का आह्वान

→ पीएम पोषण द्वारा जनजातीय बच्चों को कुपोषण से मुक्ति

→ सुरक्षित मातृत्व योजना, जननी सुरक्षा योजना, मिशन इन्द्रधनुष द्वारा जनजातीय महिलाओं को स्वास्थ्य

→ आयुष्मान कार्ड, डिजिटल आयुष्मान योजना द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा

अतः सरकार को निजी प्रयासों को भी इसमें अपनाना चाहिए तथा प्रशासन, नागरिक समाज द्वारा जागरूकता व योजना पहुँचाना चाहिए।

12. विधायी अंग के रूप में संसदीय कार्यों की गणना कीजिये। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि संसदीय संस्था और उसकी प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाने हेतु सुधार एवं तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई अनिवार्य है? (250 शब्द) 15

Enumerate the functions of Parliament as the legislative organ. Do you agree that reforms and urgent remedial action seem imperative for making parliamentary institutions and processes effective?

(250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत मे ब्रिटेन की तरह संसदीय व्यवस्था अपनायी गयी है। परंतु यह संसदीय सर्वोच्चता की जगह संविधान की सर्वोच्चता है। ऐसे मे संसद कानून निर्माण की सबसे बड़ी संस्था है।

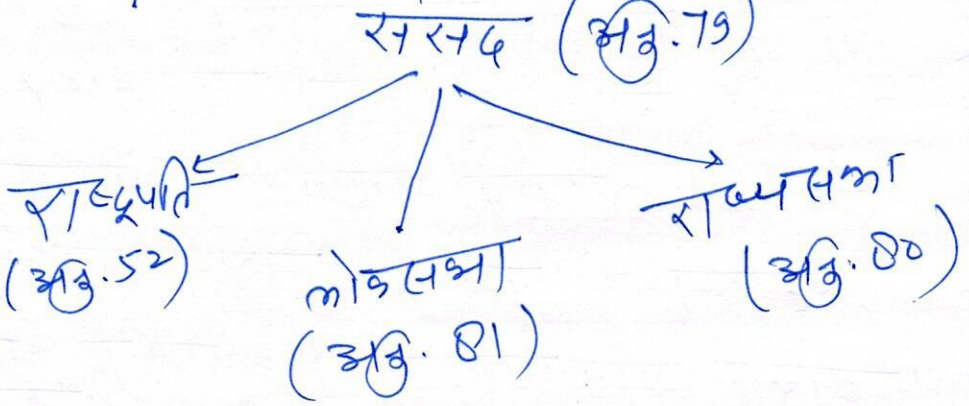

विधायी अंग के रूप मे संसद →

① संविधान संशोधन, नए विधेयक का निर्माण, नए राज्य निर्माण

आदि मे संसद कार्य करती है)

② यह बजट को पास करती तथा धन का आवंटन करती |

③ यह कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती

निंदा प्रस्ताव

कटौती प्रस्ताव

प्रश्न पूछकर

④ यह लोकसभा, राज्यसभा मे विभिन्न चरणो द्वारा विधेयक को पास करती तथा बाद मे राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते |

⑤ इसकी समितियाँ विधेयक निर्माण मे सहायक जैसे - वक्फ बिल ज्वाइंट कमिटि के पास गया |

चुनौतियाँ

① कार्य के घण्टे व दिवस कम होते जा रहे जैसे → 1950 → 126 घण्टे
2024 → 60 घण्टे

② अधिकांश विधेयक बिना समितियों के पास भेजे पास

③ हंगामे और कोरम का बढ़ता प्रभाव

④ अध्यादेशों की बढ़ती संख्या इसके विधे. निर्माण > शामिल वर्ग

ऐसे मे कुछ सुधार

① कार्यदिवसो की संख्या बढ़ाना 1950 के स्तर 125-30 तक ले जाना

② विधेयक पर समितियों के सुझाव मानना

③ अध्यादेश को न्यून करना

④ रचनात्मक आलोचना करना

अत: भारत के लोकतंत्र को बनाए रखने और जवाबदेही व उत्तरदायित्व को बनाए रखते हुए भारतीय संसद को उच्च नैतिक मानको का पालन करना चाहिए |

13. वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र कम विरोधाभासी होने के साथ विवादों को सुलझाने के पारंपरिक तरीकों का बेहतर विकल्प प्रदान कर सकते हैं। चर्चा कीजिये। इस दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गए हैं? (250 शब्द) 15

Alternate Dispute Resolution mechanisms are less adversarial and can provide a better substitute to the conventional methods of resolving disputes. Discuss. What are the government's efforts to bring out a transformative shift towards it? (250 words) 15

वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) से तात्पर्य है न्यायालय के अतिरिक्त मध्यस्थता, सुलह, समझौते आदि से न्याय प्रदान करना। वर्तमान में 5 करोड़ केस पेंडिंग है ऐसे में इनका महत्व → मध्यस्थता अधि. 2023

(1) यह प्राकृतिक न्याय पर कार्य करता है। यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से बंधा नहीं है।

(2) यह सुलभ, शीघ्र व सरलता से न्याय प्रदान करता है।

(3) लोक~~पाल~~ अदालत जैसी संस्था के निर्णय बाध्यकारी है जो न्याय पर बोझ को कम करते।

(4) मध्यस्थता कोर्ट लोगो को आपस मे विवाद सुलझाकर एक आर्थिक समझौता करवाते है।

(5) यह पारंपरिक तरीको की जगह बिना वकील के तथा साक्ष्य अधिनियम के बिना स्वंय खुद व्यक्ति द्वारा अपनी बात रखने व केस लड़ने का मंच है

(6) लोकअदालत केस को न्याया. से अलग शांतिपूर्ण रूप से विवाद हल करवा सकते।

(7) ग्राम न्यायालय ग्राम स्तर पर लोगो को सस्ता व सुलभ न्याय उपलब्ध करवा सकते।

सरकार के प्रयास

① सरकार ने मध्यस्थता विधेयक 2023 को अब अधि. बन चुका है Arbitration Court की स्थापना

② नालसा अधि० 1987 द्वारा लोक-अदालत का प्रावधान

③ ग्राम न्यायालय अधि० 2008 द्वारा ई-कोर्ट गाँवो मे

④ ग्राम सभा को सिविल शक्तियाँ

⑤ हाल ही में गांधीनगर मे GIFT सिटी मे IFC की तर्ज पर प्राइवेट मध्यस्थता की व्यवस्था।

कुछ चुनौतियाँ
- → लोक अदालतों की कमी
- → ग्राम न्यायालय के लिए फंड व अवसंरचना की कमी
- → मध्यस्थता कोर्ट की जागरूकता का अभाव
- ↓ लोगो मे जागरूकता नही

अतः केस पेंडिंग को खत्म करने और सुलभ न्याय मे ADR मील का पत्थर सिद्ध हो सकते।

14. दिल्ली के शासन और भारत के संघीय ढाँचे पर इसके संभावित प्रभाव पर विचार करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (GNCTD) (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

(250 शब्द) 15

Critically examine the provisions of the Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD) (Amendment) Act, 2023 considering its potential impact on the governance of Delhi and the federal structure of India.

(250 words) 15

69 वें संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसको विशेष शक्ति दी गई जहाँ विधानसभा होगी। यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रावधान है जो केन्द्र/राष्ट्रपति का प्रशासक है।

अभी हाल ही में सिविल सर्विस को लेकर कि किसके अधिकार क्षेत्र मे है? उस पर न्यायालय (SC) का निर्णय दिल्ली सरकार के पक्ष मे आया जहाँ कहा गया कि →

① मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद चुनी हुई सरकार है तथा संसदीय व्यवस्था मे सिविल सेवक सरकार के प्रति उत्तरदायी। इसलिए दिल्ली सीएम व मंत्रियो को उनकी ट्रांसफर, पोस्टिंग को लेकर अधिकार है।

② लोकप्रशासन, भूमि व पुलिस को छोड़कर दिल्ली सरकार उनका प्रयोग कर सकती है

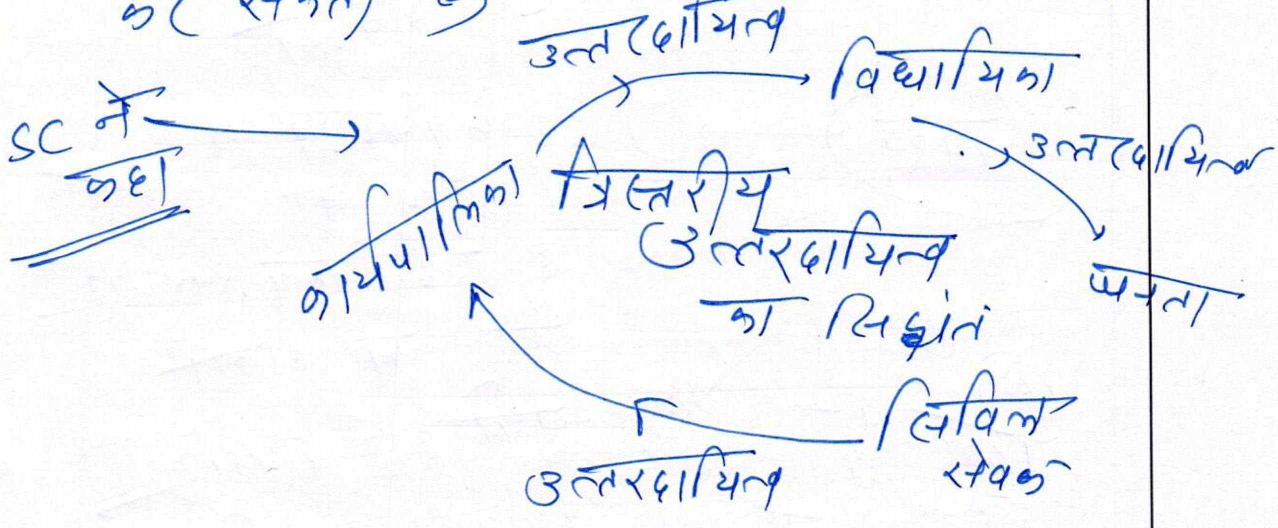
SC ने कहा
त्रिस्तरीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत
कार्यपालिका
उत्तरदायित्व
विधायिका
उत्तरदायित्व
जनता
सिविल सेवक
उत्तरदायित्व

केंद्र सरकार एक अध्यादेश द्वारा इस निर्णय मे सुधार करती है। तथा GNCTD (संशोधन) 2023

के प्रावधान
- ① समिति
  - CM दिल्ली
  - सचिव गृह
  - मुख्य सचिव (दिल्ली)
- ② बहुमत से निर्णय

पक्ष
- ① न्यायिक विधायन नहीं होना चाहिए यह संसद का कार्य है
- ② दिल्ली एक विशेष क्षेत्र है जहाँ NCT है।
- ③ AGMUT कैडर के अधिकारी केन्द्र के अधीन

विपक्ष
- ① SC के निर्णय के विरोध मे
- ② उत्तरदायित्व सरकार का कम होगा
- ③ चुनी हुई सरकार संघवाद के विरोध
- ④ दिल्ली पर केन्द्र का नियंत्रण

अतः संघीय शासन को बनाए हुए इस राजनीतिक विवाद को संयम व संतुलन के साथ हल करना चाहिए।

15. भारतीय लोकसभा और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में अध्यक्ष की भूमिका की तुलना कीजिये। चर्चा कीजिये कि ये भूमिकाएँ अपने-अपने विधायी निकायों की कार्यप्रणाली को कैसे प्रभावित करती हैं। (250 शब्द) 15

Compare and contrast the role of speaker in the Indian Lok Sabha and British House of Commons . Discuss how these roles impact the functioning of their respective legislative bodies. (250 words) 15

भारत और ब्रिटेन दोनो मे संसदीय शासन अपनाया गया है। जहाँ ब्रिटेन मे संसदीय सर्वोच्चता है तो वहीं भारत मे संविधान की सर्वोच्चता है। ऐसे मे अध्यक्ष के पद को लेकर प्रावधान → अंतर दोनो मे

⇓

ब्रिटेन → "एकदा स्पीकर सदैव स्पीकर"

→ यहाँ स्पीकर एक बार चुन जाने के बाद वह अपने दल से इस्तीफा दे देता है।

→ वह सर्वसम्मति से चुना

जाता है

→ वह अपने पद पर जब तक चाहे तब तक रहता है

→ वह किसी भी दल का समर्थन नहीं करता।

→ यह संसद की कार्यवाहियों में लेबर व कन्सरवेटिव दोनों पार्टियों को समान महत्व देता है

भारत

→ यह दल से जुड़ा होता है

→ यह जिसकी सरकार होता है उसका ही होता है।

→ यह पाँच साल या

अगले लोकसभा की पहली कार्यवाही तक बना रहता है।

→ यह कास्टिंग वोट में अपने दल का समर्थन करता

→ दलबदल अधि० के समय यह पक्षपातपूर्ण कार्यवाही करता है।

समानता - दोनों में

① संसद की कार्यवाही का संचालन

② नियमों, कार्यवाहियों का निर्माण

③ संसद का डेकोरम बनाए रखते

④ धन विधेयक को घोषित

अतः ब्रिटेन के अध्यक्ष के बारे में कहा जाता है " उसके पोशाक ही संसद में शांति के लिए पर्याप्त है।" जबकि भारत में कई बार अध्यक्ष पर दल को लेकर आरोप लगते हैं फिर भी भारतीय अध्यक्ष ने अभी तक अच्छा कार्य किया है।

16. राजकोषीय संघवाद सुनिश्चित करने एवं केंद्र और राज्य सरकारों की राजकोषीय शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने में वित्त आयोग की महत्त्वपूर्ण भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द) 15

Critically evaluate Finance Commission's crucial role in ensuring fiscal federalism and maintaining a balance between the fiscal powers of the central and state governments. (250 words) 15

संघीय व्यवस्था मे भारत मे राजकोषीय संघवाद का झुकाव केन्द्र की तरफ है। ऐसे मे अनु. 280 मे वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। जो पांच वर्षो पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

वित्त आयोग

Ⓐ Vertical विभाजन < केन्द्र / राज्य } 15 FC ने 41%

Ⓑ Horizontal विभाजन < राज्य / राज्य

15 FC ने

आय असमानता	जनसंख्या	क्षे.	डेमोग्राफिक
45%	15%	15%	10%

- ... etc.

वित्त आयोग का महत्व

→ यह केन्द्र द्वारा राज्यों को पारदर्शी व सुलभ वित्त उपलब्ध

→ अनु. 275 के अनुदान मे सिफारिश करता

→ आपदा फण्ड मे सहायता

→ इसने नगरीय प्रशासन मे सलाह दी [15FC → शर्त सहित

10 लाख (+) — 10 लाख कम जनसंख्या

10 लाख (+) → 60% — 40% अनुदान

60% L कचरा प्रबंधन जल प्रदाता

40% अनुदान → विशेष उपचार शर्त रहित

→ यह 73 वें व 74 वें संशोधन द्वारा पंचायतो व नगरीय प्रशासन फण्ड की समस्या दूर करने सलाह

[वित्त आयोग की आलोचना]

→ इसका विभाजन दक्षिण राज्यों के विरोध मे है। (आय असमानता जनसंख्या उत्तर मे ज्यादा

→ यह राज्य सूची के विषय पर हस्तक्षेप (15FC: शर्त सहित अनुदान की व्यवस्था)

→ यह अनुदान को शर्त सहित बना रहा जो पहले अनु. 275 के तहत स्वायत्त मिलते थे

→ 42% से घटाकर (15 वें FC ने 41% कर दिया

→ इसके पास खुद की मशीनरी व अवसंरचना व डेटा की कमी है जिससे ये सही विभाजन नहीं कर पाता।

अतः सरकार को इसे UPSC, EC की तरह संस्था बना देना चाहिए। वर्तमान में 16 वें FC का गठन हो चुका है)

17. क्या भारत ने अपनी वैश्विक स्थिति और प्रभाव को बढ़ाने के लिये अपनी सॉफ्ट पावर का लाभ उठाया है? विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

Has India leveraged its soft power to enhance its global stature and influence? Analyze. (250 words) 15

आज भारत का 30 मिलियन डायस्पोरा विदेश मे है। 'जी-20' मे 'वासुधैव कुटुम्बकम्' द्वारा भारतीय सरकार ने अपना साफ्ट पावर बढ़ाया। वर्तमान उदारीकरण व वैश्वीकरण के दौर मे सॉफट पावर हार्ड पावर की अपेक्षा अच्छा प्रतीत होता है

भारत के साफ्ट पावर और उसका लाभ →

→ अमेरिका मे 3 मिलियन डायस्पोरा है जो वहाँ दिवाली, होली, ईद और छठ पूजा मनाता है। जिससे भारतीयों के प्रति अमेरिका ने दृष्टिकोण पीवर्तित किया।

→ भारत बुद्ध सर्किट द्वारा आसियान देशो से एक्ट ईस्ट नीति को कार्यान्वयन कर रहा है

→ योगा द्वारा दुनिया मे अध्यात्म के प्रसार के रूप मे भारत को विश्व गुरु के रूप मे दिखा रहा।

→ अपनी मुस्लिम संस्कृति व मुस्लिम डायस्पोरा वेस्ट एशिया नीति का निर्माण कर रहा है साऊदी मे हज यात्रियो को सुलभता पहुँचा रहा है

→ अपने बोलीवुड फिल्मे व सॉन्ग द्वारा सेन्ट्रल एशिया मे कनेक्ट सेन्ट्रल एशिया नीति चला रहा।

→ बुद्ध कल्चर से ही जापान, कोरिया, नेपाल, श्रीलंका को जोड़ रहा।

→ भारत का डायस्पोरा पूरी दुनिया में है जो हमारी विदेश नीति में सहायक है

जैसे → अमेरिका का सिनेट काकस समूह ने 2008 की सिविल परमाणु डील में सहायता की।

कुछ चुनौतियाँ → ① अमेरिका की तरह अभी भी कोरिया, हॉलीवुड फिल्मों जैसा प्रभाव नहीं

② अल्पसंख्यक अधिकार को लेकर चुनौती

③ वर्तमान खालिस्तानी व पन्नू उदय व भारत-कनाडा संबंध में चुनौती

④ फण्ड की कमी

अतः भारत जहाँ ग्लोबल साउथ में हम समान विचारधारा लेकर चल रहे हैं तो वहीं चाइना+1 को अवसर के रूप में देख रहे। एवं सॉफ्ट पावर के साथ-2 अपनी विदेश नीति में साथ-2 सामाजिक कल्चर जोड़ रहे हैं।

18. अपनी स्थापना के बाद से पिछले दो दशकों से अधिक समय में, बिम्सटेक (BIMSTEC) ने अपनी विशाल क्षमता का उपयोग करते हुए सामूहिक उन्नति की दृष्टि वाले समूह के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने में एक लंबा सफर तय किया है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द) 15

In the past more than two decades since its establishment, BIMSTEC has come a long way in distinguishing itself as a group with a vision for collective advancement utilizing its vast potential. Comment. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

दक्षिण एशिया मे आसियान की तरह आज तक कोई समूह नही बन पाया। ऐसे मे बिमसटेक को सार्क के विकल्प के रूप मे भी देखा जाता है यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति मे भी सहायक है

बिमसटेक का महत्व

1. सार्क का विकल्प
2. एक्ट ईस्ट नीति मे सहायक, हमारे उत्तर पूर्व के विकास मे आवश्यक
3. आसियान देशो से कनेक्टिविटी का मार्ग

④ ब्लू इकोनोमी (बंगाल की खाड़ी) मे सहायक

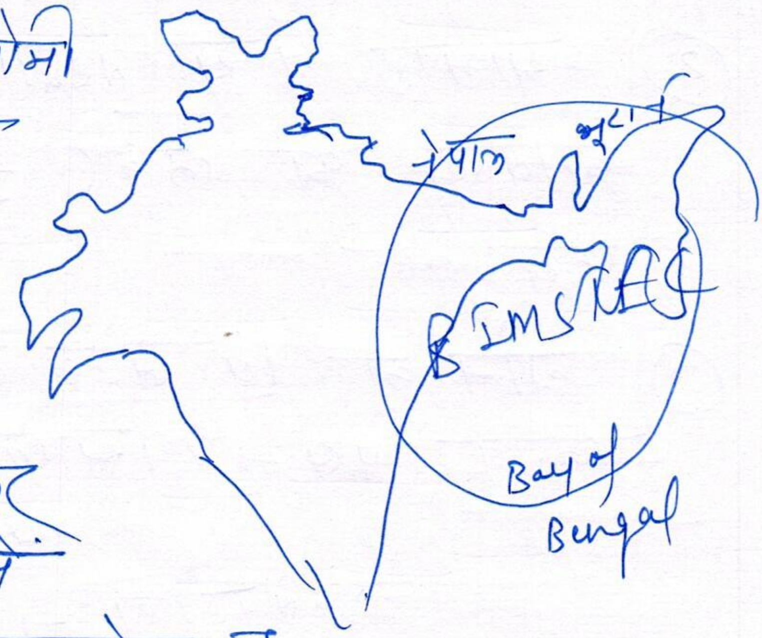
नेपाल
भूटान
BIMSTEC
Bay of Bengal

⑤ इसके ग्यारह पिलर है। जिसमें विभिन्न सहयोग हो

⑥ भारत आतंकवाद व सुरक्षा के पिलर का नेतृत्व तो बांग्लादेश कनेक्टिविटी का नेतृत्व

⑦ दक्षिण एशिया मे मुक्त व्यापार क्षेत्र, तकनीक उन्नति व जलवायु परिवर्तन मे सहायक।

चुनौतियाँ

① वर्तमान बांग्लादेश संकट ने जटिलता बढ़ा दी है।

(2) म्यांमार सैन्य तख्तापलट ने भविष्य को लेकर चुनौतियाँ पैदा की

(3) चीन का बिम्सटेक राष्ट्रों में प्रभाव फैला → सितवे बंदरगाह
(म्यांमार)
↳ हंबनटोटा → श्रीलंका
↳ कोको आयलैण्ड

→ चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति

(4) भारत को लेकर बिग ब्रदर सिंड्रोम

(5) अभी भी व्यापार मात्र $70 B का।

(6) डेफिसिट डिलीवरी

अतः भारत को गुजराल डाक्ट्रिन, नेबरहुड फर्स्ट नीति अपनाते हुए इसे जोन ऑफ पीस में बदलने की आवश्यकता है

19. उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते वैश्विक ऋण संकट के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पड़ने वाले प्रमुख परिणामों का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

Examine the major outcomes of soaring global debt crisis in emerging and developing economies on international relations. (250 words) 15

आज कोविड के बाद दुनिया का एक बड़ा भाग मंदी को महसूस कर रहा है। अभी 2022 में श्रीलंका के आर्थिक संकट ने दुनिया का ध्यान खींचा है।

ऐसे में वैश्विक गहरा संकट और अन्तर्राष्ट्रीय संबंध →

परिणाम

① श्रीलंका के आर्थिक संकट ने उसकी सम्प्रभुता को चुनौती दी। चीन की चेकबुक कूटनीति ने श्रीलंका को डेब्ट ट्रेप मे फंसा लिया जिससे उसे अपने हंबनटोटा बंदरगाह को गिरवी रखना पड़ा।

② आज कई उभरती अर्थव्यवस्था यथा अफ्रीका में, लैटिन व द० अमेरिका में वित्त संकट का सामना कर रही है

जैसे → अर्जेन्टीना

③ सम्प्रभुता के साथ-2 नीतियाँ भी प्रभावित होती है IMF (शर्त सहित राशि प्रदान करता है (Terms of Condition)/Aid)

जैसे पाक को IMF बेल आउट पैकेज

④ राष्ट्रों की सुरक्षा को खतरा (नौसेनिक/सैनिक अड्डे)

⑤ पड़ोसी राष्ट्र से संबंध खराब।

आज चीन CPEC द्वारा POK से रोड निकाल रहा है जो भारत के लिए खतरा

⑥ भारत 1990 मे अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ा था जो हमारी विदेश नीति मे हस्तक्षेप था।

⑦ आज अफ्रीका के कई राष्ट्र अपने संसाधनो को चीन के सौंप चुके है
जैसे - कांगो, बोत्सवाना, जिबूती

⑧ स्ट्रिंग आफ पर्ल्स द्वारा चीन हिन्द महासागर के द्वीपीय देशों पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा जो भारत की हिन्द प्रशांत की राजनीति मे खतरा है

अतः राष्ट्र की सम्प्रभुता अखण्डता, उसकी नीति आदि सभी नया संकट के कारण प्रभावित होती है

20. यूरोप का हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर बढ़ता ध्यान तथा भारत के साथ गहराता आर्थिक और तकनीकी सहयोग परस्पर लाभ प्रदान करता है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Europe's increased focus on the Indo-Pacific and the deepening economic and technological collaboration with India offer mutual benefits. Discuss. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत और यूरोप दोनो लोकतंत्र व उदार विश्व की समर्थक है दोनो नियम आधारित विश्व का समर्थन करते हैं। साझी चिंता के रूप मे दोनो को चीन से खतरा है।

भारत और यूरोप

① हिन्द प्रशांत मे चीन के शक्तिशाली उभार के कारण भू-राजनीति का फोकस है। यूरोप तथा अमेरिका भारत के साथ चीन को हिन्द प्रशांत मे संतुलित करना चाहता है ऐसे मे अमेरिका का AUKUS सैन्य

प्रतिबंधन तथा व्यापार महत्वपूर्ण है। तथा ब्लू इकोनोमी की एक विकल्प है

(2) जी-20 में चीन के OBOR को प्रतिसंतुलित व स्वेज नहर के विकल्प के रूप में IMEEC का (एशिया से यूरोप) विचार रखा गया। (India Middle east Economic Corridor)

(3) भारत सरकार ब्लू-अर्थनीति पर भी ध्यान दिए हुए है इसलिए EU के साथ FTA वार्ता चल रही जबकि अभी हाल ही में EFTA समझौता हुआ

स्विट्ज़रलैंड नॉर्वे आइसलैंड लिंचेस्टीन

(4) पश्चिम ~~एशिया~~ यूरोप भारत सरकार के हमेशा ध्यान में

रहा है परंतु अब विदेश नीति यूरोप के Big-4 (ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस) से बाहर आकर सेन्ट्रल यूरोप पर ध्यान दे रही जैसे - मोदी जी की हाल में आस्ट्रिया, पोलैण्ड, यूक्रेन वार्ता।

(5) चूँकि भारत महाशक्ति बनने की आकांक्षा रखता है इसलिए यूक्रेन संघर्ष में मोदी जी कूटनीति द्वारा पीस स्थापित करना चाहते हैं इसलिए उनकी यात्रा।

कुछ चुनौतियाँ

① यूक्रेन संघर्ष में रूस के पक्ष लेकर

② FTA में फायटो सैनिटरी मुद्दे

③ कार्बन टैक्स

④ WTO में IPR मुद्दे

अतः वर्तमान अनिश्चित दुनिया में भारत अपने संबंधों को विविधीकृत करते हुए यूरोप से संबंधों पर बल दे रहा है।

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)